



वर्श्व में ख़ादय सुरकषा और पोषण की स्थति(SOFI) 2023

प्रलिमिंस के लयि:

[संयुक्त राषट्र ख़ादय एवं कृषि संगठन \(FAO\)](#), [ब्रकिंस राषट्र](#), [PPP डॉलर](#), [वैशवकि ख़ादय सुरकषा सूचकांक 2022](#), [मानव वकिस रपिरट 2021-22](#), [वैशवकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक \(MPI\) 2022](#), वैशवकि ख़ादय सुरकषा सूचकांक 2022, राषट्रीय ख़ादय सुरकषा अधनियिम (NFSA) 2013, न्यूनतम समर्थन मूलय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), राषट्रीय बागवानी मशिन, राषट्रीय ख़ादय प्रसंस्करण मशिन

मेन्स के लयि:

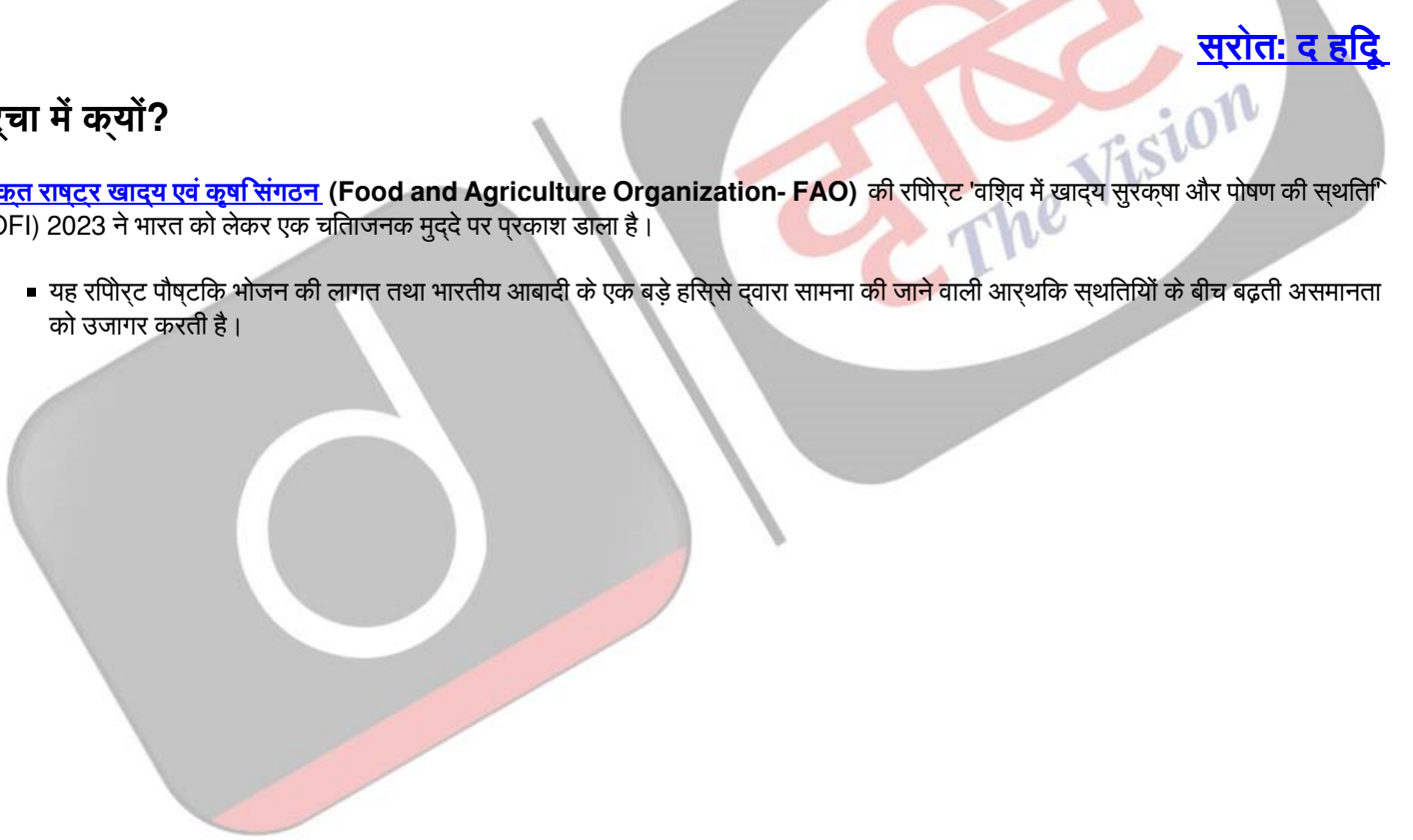
ख़ादय सुरकषा और राषट्रीय सुरकषा, ख़ादय सुरकषा एवं संबंधति मुददे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यौं?

[संयुक्त राषट्र ख़ादय एवं कृषि संगठन \(Food and Agriculture Organization- FAO\)](#) की रपिरट 'वर्श्व में ख़ादय सुरकषा और पोषण की स्थति' (SOFI) 2023 ने भारत को लेकर एक चतिजनक मुददे पर प्रकाश डाला है ।

- यह रपिरट पौष्टिक भोजन की लागत तथा भारतीय आबादी के एक बड़े हसिसे द्वारा सामना की जाने वाली आर्थकि स्थतियों के बीच बढ़ती असमानता को उजागर करती है ।



Not enough on the plate

The data for the charts were sourced from a blog published by the World Bank titled, 'Over 3.1 billion people could not afford a healthy diet in 2021, an increase of 134 million since the start of COVID-19,' and the 'State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2023'

Chart 1: The chart shows the cost of a healthy diet in terms of PPP dollars per person per day in 2021, the latest year with comparable data

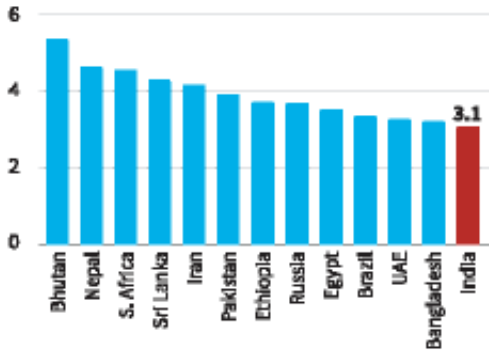


Chart 2: The chart shows the share of the population that is unable to afford a healthy diet in 2021. For instance, in India, 74% were not able to afford a healthy diet

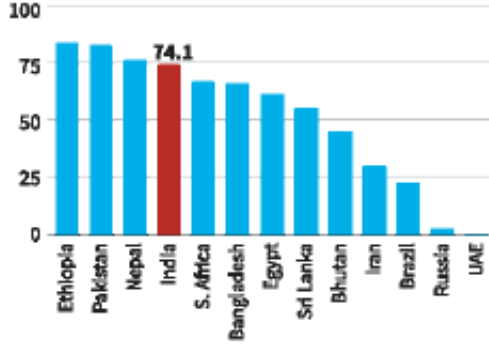


Chart 3: The chart shows the change (in %) in the cost of a healthy diet over the years across regions

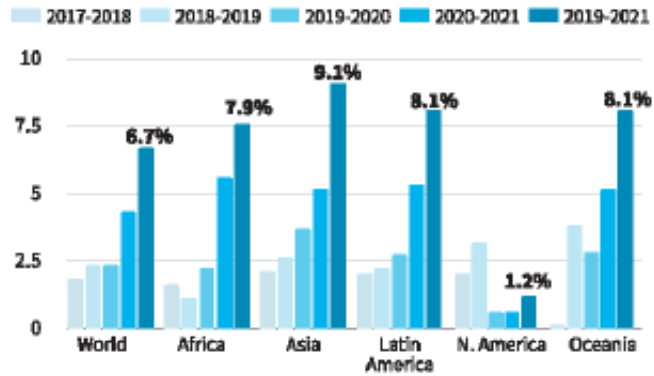
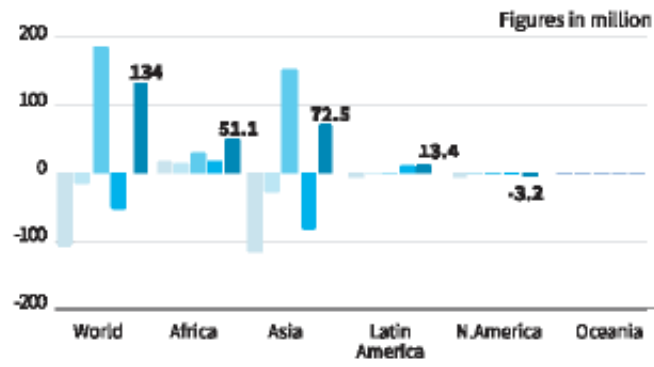


Chart 4: The chart shows the change in the number of people (in million) who were unable to afford a healthy diet over the years across regions



रिपोर्ट के प्रमुख बंदि:

- वैश्विक भुखमरी:** वैश्विक भुखमरी की स्थिति विरुध 2021 और वरुध 2022 के बीच स्थिर बनी हुई है, **महामारी**, जलवायु परिवर्तन तथा यूकरेन में युद्ध सहति संघर्षों के कारण **वरुध 2019 के बाद** से पूरे विश्व में भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या **122 मिलियन से अधिक बढ़ गई है**।
- पौष्टिक भोजन तक पहुँच:** वरुध 2022 में लगभग 2.4 बलियन व्यक्तियों, मुख्य रूप से महिलाओं और ग्रामीण कषेत्रों के नवासियों की पौष्टिक, सुरकषति एवं पर्याप्त भोजन तक पहुँच में लगातार कमी देखी गई है।
- बाल कुपोषण:** बाल कुपोषण की स्थिति अभी भी चिंताजनक रूप से बनी हुई है। वरुध 2021 में 22.3% (148.1 मिलियन) बच्चे अवकिसति थे, 6.8% (45 मिलियन) कमजोर थे तथा 5.6% (37 मिलियन) अधिक वजन वाले थे।
- शहरीकरण का आहार पर प्रभाव:** जैसे-जैसे शहरीकरण में तेज़ी आती है, प्रसंस्कृत तथा सुवधिजनक खाद्य पदार्थों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही नगरीय, उप-नगरीय एवं ग्रामीण कषेत्रों में अधिक वजन और मोटापे वाली जनसंख्या की दर में वृद्धि होती है।
- वैश्विक बाज़ारों पर ग्रामीण निर्भरता:** विशेष रूप से अफ्रीका एवं एशिया में आत्मनिर्भर ग्रामीण कषेत्र, अब तेज़ी से राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य बाज़ारों पर निर्भर होते जा रहे हैं।
- कषेत्रीय रुझान:** SOFI रिपोर्ट वभिन्न कषेत्रों में स्वस्थ आहार की लागत और सामर्थ्य में बदलाव पर भी नज़र रखती है।
 - वरुध 2019 और 2021 के बीच एशिया में स्वस्थ आहार बनाए रखने की लागत में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, **जो लगभग 9% बढ़ गई**।
 - पौष्टिक आहार लेने में असमर्थ लोगों की संख्या में वृद्धि एशिया और अफ्रीका में सबसे अधिक थी, दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एवं पश्चिमी अफ्रीका को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- दक्षिण एशिया का संघर्ष:** 1.4 अरब लोगों के साथ दक्षिण एशिया में स्वस्थ आहार का खर्च उताने में असमर्थ व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक (72%) दर्ज की गई।
- अफ्रीका की चुनौती:** अफ्रीका में पूर्वी एवं पश्चिमी अफ्रीका विशेष रूप से प्रभावित हुए, जहाँ 85% आबादी स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ थी। इन दो महाद्वीपों (एशिया और अफ्रीका) ने वैश्विक स्तर पर इस आँकड़े में वृद्धि में 92% योगदान दिया, जो अफ्रीकी महाद्वीप को लेकर मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करता है।
- भविष्य का दृष्टिकोण:** यह अनुमान लगाया गया है कि वरुध 2050 तक वैश्विक आबादी का 70% शहरों में नवास करेगा। इस महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव हेतु इस नई शहरी आबादी को भुखमरी, खाद्य असुरकषा एवं कुपोषण को पूर्ण रूप से खतम करने के लिये खाद्य प्रणालियों की

भारत के संदर्भ में रपिपोर्ट से संबंधित मुख्य बडि:

- **भारत में स्वस्थ आहार की लागत:** SOFI रपिपोर्ट के अनुसार, **BRICS देशों** और उनके पड़ोसियों के मध्य स्वस्थ आहार की लागत भारत में सबसे कम है। वर्ष 2021 में भारत में स्वस्थ आहार की लागत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन लगभग 3.066 डॉलर **करय शकतिसमता (PPP)** है, जो वास्तव में इसे वहन योग्य बनाती है।
 - यदि आहार की लागत देश की औसत आय का 52% से अधिक हो तो इसे अप्राप्य माना जाता है। अन्य देशों की तुलना में भारत की औसत आय कम है।
 - इससे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये अनुशंसित आहार का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है।
- **मुंबई केस स्टडी:** यह रपिपोर्ट मुंबई के मामले में एक विशिष्ट केस स्टडी पर भी प्रकाश डालती है, जहाँ **मात्र पाँच वर्षों में भोजन की लागत 65% तक बढ़ गई है।** इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान वेतन और मज़दूरी में केवल 28%-37% की वृद्धि हुई है।
 - नरितर डेटा उपलब्धता हेतु चयनित मुंबई, भारत में शहरी आबादी के समक्ष आने वाली चुनौतियों का एक ज्वलंत उदाहरण है।
- **वैश्विक तुलना/मलिन:** इस रपिपोर्ट में भारत की अन्य देशों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में स्वस्थ आहार की लागत अपेक्षाकृत कम है लेकिन आय असमानताओं के कारण यह आबादी के एक बड़े हिस्से के लिये अप्राप्य है।
 - वर्ष 2021 में 74% भारतीय स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ थे, जिससे भारत को अन्य देशों की तुलना में विश्व में चौथे स्थान पर रखा गया।

भारत के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिती करने का महत्त्व:

- **जनसंख्या की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना:**
 - भारत में एक बड़ी आबादी कुपोषित अथवा अल्पपोषित है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है।
 - **वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022** के अनुसार, भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 16.3% है। इसके अलावा भारत में 30.9% बच्चे अवकिसिती हैं, 33.4% न्यून-भार वाले हैं तथा 3.8% मोटापे से ग्रस्त हैं।
- **आर्थिक विकास को समर्थन:**
 - कृषि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिती कर सरकार किसानों का समर्थन कर सकती है और उनकी आय को बढ़ा सकती है, जिससे आर्थिक विकास को गति देने में मदद मिल सकती है।
 - भारत की 70% से अधिक आबादी कृषि संबंधी गतिविधियों में संलग्न है, यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ का निर्माण करती है।
- **नरिधनता कम करना:**
 - खाद्य सुरक्षा नरिधनता के स्तर को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कफियती/वहनीय और पोषक खाद्य तक पहुँच प्रदान करने से लोग अपने खर्चों का बेहतर परबंधन कर सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम कर सकते हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।
 - **वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक** (Multidimensional Poverty Index- MPI) 2022 के अनुसार, भारत में गरीबों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है (22.8 करोड़), जिसके बाद दूसरा स्थान नाइजीरिया का है (9.6 करोड़)।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चिती करना:**
 - भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खाद्य सुरक्षा भी आवश्यक है। स्थिर खाद्य आपूर्ति सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पर अंकुश लगा सकती है, जनिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होता है।
- **जलवायु परिवर्तन का मुकाबला:**
 - जलवायु परिवर्तन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा है। सतत/संवहनीय कृषि अभ्यासों को अपनाकर और जलवायु-प्रत्यास्थी फसलों में निवेश कर, भारत बदलती जलवायु के प्रति बेहतर अनुकूलन स्थिति प्राप्त कर सकता है तथा अपनी आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिती कर सकता है।
 - अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आकलन (International Food Security Assessment, 2022-2032) इंगति करता है कि भारत की विशाल आबादी का खाद्य असुरक्षा प्रवृत्तियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में लगभग 333.5 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।

संबंधित पहलें:

- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(National Food Security Act- NFSA\) 2013](#)
- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन \(National Food Security Mission\)](#)
- [राष्ट्रीय कृषि बाजार \(e-NAM\) प्लेटफॉर्म](#)
- [राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन \(National Food Processing Mission\)](#)
- अन्य नीतियाँ:
 - [कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#)
 - [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#)
 - [राष्ट्रीय बागवानी मिशन \(National Horticulture Mission\)](#)

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ:

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:
 - अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण किसानों के लिये अपनी उपज को बाजार तक ले जाना और उसका उचित भंडारण करना मुश्किल हो जाता है। इससे अधिक कृषक होते हैं और किसानों को कम लाभ होता है।
- खराब कृषिपद्धतियाँ:
 - कृषि भूमि तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं अनुचित संचाई तकनीकों जैसी खराब कृषिपद्धतियों के कारण मृदा की उर्वरता और फसल की पैदावार में कमी आई है।
- जटिल मौसम की स्थिति:
 - जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की जटिल स्थितियों के कारण भी फसल बर्बाद होती है और खाद्यान्न की कमी हो रही है। बाढ़, सूखा और लू की घटनाएँ लगातार और तीव्र होती जा रही हैं, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है तथा कीमतें बढ़ जाती हैं।
- अकुशल आपूर्ति शृंखला नेटवर्क:
 - अपर्याप्त परिवहन, भंडारण और वितरण सुविधाओं सहित अकुशल आपूर्ति शृंखला नेटवर्क भी भारत में खाद्य असुरक्षा में योगदान करते हैं। इससे उपभोक्तों के लिये खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाती हैं और किसानों को कम लाभ प्राप्त होता है।
- खंडित भूमि जोत:
 - खंडित भूमि जोत, जहाँ किसानों के पास ज़मीन के छोटे और बखिरे हुए भूखंड हैं, आधुनिक कृषिपद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाना मुश्किल बनाते हैं। यह खाद्य उत्पादन और उपलब्धता को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- कृषि उत्पादन प्रणालियों और अनुसंधान में निवेश:
 - सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिक कृषि अनुसंधान में निवेश करना चाहिये।
- भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क में सुधार:
 - सरकार को फसल के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिये पर्याप्त भंडारण सुविधाएँ विकसित करनी चाहिये और आपूर्ति-मांग संतुलन सुनिश्चित करने के लिये देश भर में खाद्य उत्पादों को वितरित करने हेतु मज़बूत परिवहन नेटवर्क विकसित करना चाहिये।
- सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी को बढ़ावा देना:
 - सरकार को कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न उपलब्धता में सुधार के लिये सार्वजनिक एवं नज़ी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।
- सतत कृषिपद्धतियों को प्रोत्साहित करना:
 - सरकार को सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिये जो मृदा की गुणवत्ता को संरक्षित करती हैं और हानिकारक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता को कम करती हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

?????????:

प्रश्न. विवाद नपिटान के लिये संदर्भ बढि के रूप में अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के उपयोग के संबंध में WTO नमिनलखिति में से कसिके साथ सहयोग करता है? (2010)

- (a) कोडेक्स एलमिंटेरियस आयोग
- (b) इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज़र्स
- (c) मानकीकरण के लिये अंतरराष्ट्रीय संगठन
- (d) विश्व मानक सहयोग

उत्तर: (a)

- कोडेक्स एलमिंटेरियस या "खाद्य कोड" कोडेक्स एलमिंटेरियस आयोग द्वारा अपनाए गए मानकों, दशा-नरिदेशों और अभ्यास संहिताओं का एक संग्रह है।
- आयोग संयुक्त FAO/WHO खाद्य मानक कार्यक्रम का केंद्रीय हसिसा है और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा तथा खाद्य व्यापार में नषिपक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये FAO एवं WHO द्वारा स्थापति कयिा गया था।

प्रश्न. FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को 'सार्वभौमिक रूप से महत्त्वपूर्ण कृषि विरसित प्रणाली (Globally Important Agricultural Heritage Systems- GIAHS)' की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? (2016)

1- अभनिरिधारति GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए।

2- पारतंत्र-अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित परदृश्य (लैंडस्केप), कृषि जैवविविधता तथा स्थानीय समुदायों के ज्ञानतंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना ।

3- इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न-भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) की हैसियत प्रदान करना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

??????:

प्रश्न.आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-sofi-2023>

